नईदुनिया

ग्लैम अप फेस्ट 2026 : जेन-जी और नान-मेट्रो इंडिया की वजह से फ्लिपकार्ट ब्यूटी में 50 फीसदी की ग्रोथ

नई दिल्ली

ई-कामर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसकी ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी में साल-दर-साल 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस प्लेटफार्म पर अब ब्यूटी से जुड़ी कुल खरीदारी में से करीब 60 फीसदी खरीदारी जेन-जी कर रहे हैं।

ई-कामर्स मार्केटप्लेस, फ्लिपकार्ट की ओर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्लैम अप फेस्ट 2026 के चौथे एडिशन में यह जानकारियां सामने आईं, जिसमें 100 से ज्यादा बड़े ब्यूटी ब्रांड्स और 6 हजार से ज्यादा क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ शामिल हुए। इस इवेंट में फ्लिपकार्ट ने अपना ग्लोबल लक्स ब्यूटी स्टोर भी लान्च किया, जिसका अनावरण जाह्नवी कपूर ने किया।

ग्लैम अप फेस्ट 2026 में फ्लिपकार्ट ने क्वांटम कंज्यूमर साल्यूशंस के साथ मिलकर तैयार की गई अपनी एनुअल ब्यूटी ट्रेंड्स रिपोर्ट 2.0 जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय खरीदारों के ब्यूटी के प्रति बदलते नजरिए को दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अब प्लेटफार्म पर ब्यूटी से जुड़ी कुल खरीदारी में से लगभग 60 फीसदी खरीदारी जेन-जी कर रहे हैं। इस तेज़ी को बढ़ाने में टियर 2 और टियर 3 शहरों के खरीदारों की बड़ी भूमिका है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, एक समय लोग सौंदर्य को सिर्फ अपनी आकांक्षाओं वाली श्रेणी मानते थे, लेकिन आज इसे आत्म देखभाल और व्यक्तिगत पहचान की रोजाना जरूरत के रूप में देख रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर ब्यूटी से जुड़ी हर तीन में से दो सर्च नान-मेट्रो शहरों से आती हैं। कटक, बर्धमान, गोरखपुर, कोट्टायम, गुंटूर, जामनगर और सांगली जैसे कई शहर देश में ब्यूटी ट्रेंड्स और खरीदारी के फैसलों को तेज़ी से आकार दे रहे हैं। ई-कामर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल (बीपीसी) उत्पाद बाजार के वर्ष 2030 तक 39 अरब यूएस डालर पर पहुंचने का अनुमान है।

ग्लैम अप फेस्ट 2026: हर पल के लिए ब्यूटी - ग्लैम अप फेस्ट 2026 इवेंट में फ्लिपकार्ट ने अपना ग्लोबल लक्स ब्यूटी स्टोर भी लान्च किया, जिसका अनावरण जाह्नवी कपूर ने किया। इससे भारतीय खरीदारों को डर्मा केयर, खुशबू (फ्रैगरेंस) और के-ब्यूटी जैसे इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंच मिली। इस स्टोर में 100 से ज्यादा ब्रांड्स शामिल हैं, जिनमें केल्विन क्लाइन, गुच्ची, नाटिका, यूसेरिन, मेडिक्यूब, डीअल्बा, सेटाफिल, सेरावे, ब्यूटी आफ जोसोन और टिर टिर जैसे ब्रांड्स शामिल हैं।

न्यूज ब्रीफ

यूपी में महंगी होगी बिजली! नोएडा के 2.5 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सीधा असर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली जल्द महंगी हो सकती है। इसकी शुरुआत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ढाई लाख उपभोक्ताओं से होगी, जहां नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) की 10 फीसदी छूट खत्म हो सकती है। यह फैसला उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा कंपनी की सरप्लस (अधिशेष) राशि के पुनरीक्षण के बाद आया है। नियामक आयोग ने एनपीसीएल की पहले अनुमानित 1500.62 करोड़ की सरप्लस राशि को घटाकर अब 593.81 करोड़ कर दिया है। यह निर्णय एनपीसीएल द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में वर्ष 2018 से 2025 तक के बिजली टैरिफ मामले में अपील के बाद पुनरीक्षण के तहत लिया गया। सरप्लस राशि में इस भारी कमी से एनपीसीएल को उपभोक्ताओं को मिलने वाली करीब 10 फीसदी की छूट घटानी या खत्म करनी पड़ सकती है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ जाएंगे। केवल नोएडा ही नहीं, पूरे प्रदेश में भी नया बिजली टैरिफ जल्द जारी होने वाला है, जिसमें बिजली महंगी होने की आशंका है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के इस फैसले का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की है। परिषद का दावा है कि प्रदेश की अन्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) पर भी उपभोक्ताओं का करीब 51,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बनता है। ऐसे में एनपीसीएल के इस मामले से भविष्य में अन्य कंपनियों के सरप्लस की जांच की मांग भी उठ सकती है, जिसका अंतिम फैसला नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

बान्ड बाजार की शार्ट-टर्म खुशी पर आरबीआई का ब्रेक! महंगाई बनी चिंता

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों को लुभाने के सरकार के हालिया प्रयासों ने बान्ड बाजार में जबरदस्त उछाल ला दिया है, खासकर कम अवधि वाले सरकारी बान्ड में। हालांकि यह उत्साह अल्पकालिक साबित हो सकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही बाजार से अतिरिक्त नकदी को सोखने के लिए कदम उठा सकता है। बढ़ती महंगाई की चिंताएं और बैंकिंग सिस्टम में अनुमानित भारी अधिशेष नकदी, आरबीआई को सख्ती बरतने पर मजबूर कर सकती हैं, जिससे विदेशी निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फिरने और बान्ड यील्ड में गिरावट पर ब्रेक लगने की आशंका है। 5 जून को सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों के लिए बान्ड निवेश को आसान बनाने के बाद से, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, पांच साल वाले सरकारी बान्ड की यील्ड 6.49 फीसदी तक गिर गई, जो बान्ड की बढ़ती कीमतों का संकेत है। सरकार ने रुपये को मजबूत करने और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष जमा योजनाओं और सरकारी कंपनियों को विदेशी बान्ड के जरिए पैसा जुटाने की छूट जैसे कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिससे लगभग 80 अरब डालर के निवेश का अनुमान है। हालांकि, इस तेजी पर अब भारतीय रिजर्व बैंक का रुख भारी पड़ सकता है। आरबीआई के लिए महंगाई एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। मई में थोक महंगाई दर 9.68 फीसदी पर पहुंच गई है और कमजोर मानसून की आशंकाएं कीमतों पर और दबाव डाल सकती हैं।

ब्रिटेन में 15 जुलाई से लागू होगा सामाजिक सुरक्षा समझौता, सालाना 500 करोड़ पाउंड की बचत

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (डीसीसी) या सामाजिक सुरक्षा समझौता 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह समझौता ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय कंपनियों के भारतीय पेशेवरों के लिए सालाना 500 मिलियन (करीब 5,000 करोड़) की महत्वपूर्ण बचत का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे उनकी परिचालन लागत में कमी आएगी और व्यापार सुगमता बढ़ेगी। यह द्विपक्षीय समझौता भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान के दोहरे भुगतान से छूट प्रदान करता है, बशर्ते वे भारत में पहले से ही योगदान दे रहे हों। दो सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से ब्रिटेन में कार्यरत लगभग 75,000 भारतीय इंट्रा-कार्पोरेट ट्रांसफरी (अस्थायी असाइनमेंट पर काम करने वाले पेशेवर) और 900 से अधिक भारतीय कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इनमें से 90-95 फीसदी पेशेवरों को इस समझौते का लाभ मिलेगा। वर्तमान में ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को वहां के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 10 वर्षों तक निरंतर योगदान देने पर ही लाभ मिलता है, जिसका लाभ अस्थायी असाइनमेंट पर रहने वाले पेशेवरों को नहीं मिल पाता।

मर्सिडीज-बेंज ने पेश की अपनी नई एस-क्लास लग्जरी कार

नई दिल्ली

भारतीय ग्राहकों के लिए लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई एस-क्लास पेश कर दी है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार भारतीय बाजार में एस-क्लास को प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया गया है, जिससे यह न केवल अधिक शक्तिशाली बल्कि पहले से अधिक ईंधन-किफायती भी बन गई है। कंपनी ने इस प्रतिष्ठित लग्जरी सेडान के अद्यतन संस्करण को कई तकनीकी और डिज़ाइन सुधारों के साथ बाजार में उतारा है। कंपनी ने इस नई कार की शुरुआती कीमत 2.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) निर्धारित की है। फिलहाल इसे केवल एस 450 ई संस्करण में उपलब्ध कराया गया है और इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसकी डिलीवरी इस वर्ष दीपावली के आसपास मिलने की संभावना है। नई एस-क्लास की शुरुआती कीमत पुराने माडल की तुलना में लगभग 35 लाख रुपये अधिक रखी गई है, जो इसमें शामिल नई तकनीक और उन्नत शक्ति प्रणाली को दर्शाता है। भारतीय बाजार में इसका

मुकाबला मुख्य रूप से बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज से माना जा रहा है। इस नई लग्जरी कार में तीन लीटर क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक विद्युत मोटर का संयोजन दिया गया है। दोनों प्रणालियों को मिलाकर वाहन लगभग 435 ब्रेक हार्सपावर की शक्ति और 680 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करता है। कंपनी का दावा है कि यह कार केवल विद्युत शक्ति पर लगभग 115 किलोमीटर तक चल सकती है और शून्य से सौ किलोमीटर प्रति घंटे की गति केवल 5.7 सेकंड में प्राप्त कर सकती है।

इसकी बैटरी को लगभग 20 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। एस-क्लास के बाहरी स्वरूप में नई ग्रिल, विशेष सितारा आकृति वाली रोशनी और नए डिजाइन वाले पहिए दिए गए हैं। अंदरूनी हिस्सा पहले से कहीं अधिक आधुनिक और तकनीक से भरपूर बनाया गया है। भारतीय बाजार में इसे लंबे व्हीलबेस वाले संस्करण में पेश किया गया है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को भरपूर स्थान मिलता है। सीटों में वेंटिलेशन, ताप नियंत्रण और मालिश जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसका सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण नया डिजिटल सुपरस्क्रीन सिस्टम है, जिसमें बड़ी ओएलईडी स्पर्श स्क्रीन और सहयात्री के लिए अलग डिजिटल स्क्रीन उपलब्ध कराई गई है।

मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए पेश किया स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान

नई दिल्ली। अपने ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी कंपनी ने स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान नामक एक नई और सुविधाजनक रखरखाव योजना पेश की है। यह योजना निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य वाहन मालिकों को सेवा और रखरखाव से जुड़े खर्चों पर बेहतर नियंत्रण देना, भविष्य में बढ़ने वाली सेवा लागतों से बचाना और वाहन स्वामित्व के अनुभव को अधिक सुविधाजनक बनाना है। ग्राहक चाहें तो नया वाहन खरीदते समय ही इसे अपना सकते हैं, वहीं पहले से वाहन उपयोग कर रहे ग्राहक भी देशभर में स्थित किसी भी अधिकृत मारुति सुजुकी सेवा केंद्र से इसे खरीद सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन है। वाहन मालिक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विभिन्न प्रकार के सेवा पैकेज चुन सकते हैं। इनमें केवल श्रम शुल्क वाले पैकेज, पुर्जों और श्रम दोनों को शामिल करने वाले पैकेज, व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष रखरखाव सेवाएं तथा इंजन आयल और शीतलक द्रव से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। कुछ चुनिंदा पुर्जों जैसे क्लच और ब्रेक के लिए घिसावट और सामान्य उपयोग से होने वाले नुकसान की सुरक्षा का विकल्प भी उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने वाले ग्राहकों को श्रम शुल्क में कम से कम दस प्रतिशत तक की बचत हो सकती है और विभिन्न पुर्जों पर भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है। चूंकि यह एक पूर्व भुगतान आधारित योजना है, इसलिए ग्राहक सेवा पैकेज खरीदते समय ही भविष्य के रखरखाव खर्च को तय कर सकते हैं, जिससे आने वाले वर्षों में सेवा शुल्क बढ़ने की स्थिति में भी उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। निजी वाहन मालिक दो वर्ष या बीस हजार किलोमीटर से लेकर दस वर्ष या एक लाख किलोमीटर तक के विकल्प चुन सकते हैं, जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए यह सुविधा दस वर्ष या एक लाख साठ हजार किलोमीटर तक उपलब्ध होगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि यह योजना ग्राहकों को अधिक विकल्प, बेहतर सुविधा और खर्चों में पारदर्शिता उपलब्ध कराएगी, जिससे वाहन स्वामित्व को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

भारत बनेगा कुशल सेमीकंडक्टर पेशेवरों का केंद्र : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में कुशल मानव संसाधन का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने पटना में कहा कि इस क्षेत्र में 10 लाख पेशेवरों की वैश्विक कमी को देखते हुए, यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है।

मंत्री वैष्णव ने पेशेवरों की कमी को भारत के लिए बड़ा अवसर बताया

मंत्री वैष्णव ने बताया कि लगभग 800 अरब डालर का वर्तमान सेमीकंडक्टर उद्योग एक वर्ष के भीतर 1 ट्रिलियन डालर को पार कर जाएगा, जिससे 2032 तक लगभग 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। वैष्णव ने पुष्टि की कि सरकार देश में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता विकसित करने पर काम कर रही है, ताकि भारतीय छात्र वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में गिने जाएं। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से अब तक लगभग 75,000 छात्रों को आकर्षक अवसर मिले हैं, और लक्ष्य इस संख्या को 5 लाख तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और उत्पादन बढ़ने के साथ कौशल विकास कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे।

मंत्री ने अपने एसटीपीआई केंद्र के दौरे के दौरान टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने युवा उद्यमियों के साथ बातचीत की और सरकारी सहायता को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की।

बीते सप्ताह सोना 2,800 रुपए, चांदी 10,600 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई

नई दिल्ली। बीते हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत 2,800 रुपए से अधिक और चांदी 10,600 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई है, जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिली है। वैश्विक अस्थिरता और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 2,830 रुपए कम होकर 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो पहले 1,47,800 रुपए पर था। इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,793 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जिनमें उल्लेखनीय कमी आई है। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। चांदी का दाम 10,609 रुपए कम होकर 2,31,973 रुपए प्रति किलो पर आ गया है, जबकि पहले यह 2,42,582 रुपए प्रति किलो था। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम 4,170 डालर प्रति औंस और चांदी का दाम 64 डालर प्रति औंस के करीब पहुंचने के साथ ही अमेरिकी फेड के चेयरमैन केविन वार्श की ब्याज दरों में बढ़ोतरी संबंधी टिप्पणी और डालर के मजबूत होने से बुलियन मार्केट में कमजोरी आई है।

नोवो नॉर्डिस्क के सिस्टम में सेंधमारी, हैकर्स ने मांगी 2.5 करोड़ डॉलर की फिरौती

फार्मा कंपनी ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच जारी

मुंबई

फार्मास्युटिकल दिग्गज नोवो नार्डिस्क कथित साइबर हमले की चपेट में आ गई है। हैकिंग समूह ने कंपनी से 2.5 करोड़ डालर की फिरौती मांगी थी, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया है। हमलावरों ने कंपनी का 1 टेराबाइट से अधिक डेटा चुराने का दावा किया है। डेनमार्क की फार्मास्युटिकल कंपनी नोवो नार्डिस्क ने इस दावे पर संज्ञान लिया है कि उसके सिस्टम से अवैध रूप से डेटा कापी करके आनलाइन प्रकाशित किया गया है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि एक हैकिंग समूह ने कंपनी से 2.5 करोड़ डालर की फिरौती मांगी थी, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया। हैकरों ने 1 टेराबाइट से अधिक डेटा चुराने का दावा किया है। नोवो नार्डिस्क ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपने प्रमुख प्लेटफार्म पर सामान्य परिचालन बनाए रखते हुए लगातार अपने सिस्टम की निगरानी कर रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस घटना को लेकर वह संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और दुनिया भर में मरीजों को दवाओं तथा सहायक सेवाओं की अबाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि, नोवो नार्डिस्क ने कथित सेंधमारी के पैमाने या प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। कंपनी का यह बयान उन चिंताओं के बीच आया है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फिरौती के लिए निशाना बनाया जा रहा है, खासकर स्वास्थ्य सेवा और दवा जैसे अहम क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान, रोगी-संबंधित जानकारी और स्वामित्व वाले डेटा को अक्सर मूल्यवान लक्ष्य माना जाता है। हाल के समय में डेटा एक्सटार्शन (डेटा चुराकर फिरौती मांगने) की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जहां हमलावर बड़े स्तर पर डेटा चोरी का दावा करके फर्मों पर फिरौती देने का दबाव बनाते हैं। कंपनियों द्वारा अक्सर यह चेतावनी दी जाती है कि जब ऐसे दावे सार्वजनिक किए जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई हो। नोवो नार्डिस्क ने इस कथित घटना के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं दी है, माना जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों और साइबर सुरक्षा टीमों की मदद से इसकी जांच चल रही है। नोवो नार्डिस्क 1994 से भारत में सक्रिय है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में कंपनी के 1,600 से अधिक कर्मचारी हैं।

उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर एफएसएसएआई सख्त, कई फूड ब्रांड्स को नोटिस

मैरिको, फेरेरो, बीकानेरवाला समेत 14 कंपनियों पर नो एडेड शुगर व स्वच्छता उल्लंघन मामला

नई दिल्ली

खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भ्रामक दावों, ब्रांडिंग और लेबलिंग के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले कई फूड बिजनेस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ग्राहकों से मिली शिकायतों के आधार पर एफएसएसएआई ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर तत्काल सुधार के उपाय करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के नियमों के उल्लंघन पर की गई है। नियामक की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक ये नोटिस भ्रामक ब्रांड नामों, उत्पाद दावों और लेबलिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए भेजे गए हैं। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि कई खाद्य आपरेटर्स ऐसे दावे कर रहे थे जो ग्राहकों को गुमराह कर सकते थे या वैज्ञानिक प्रमाणों के बिना स्वास्थ्य लाभ का दावा करते थे। कार्रवाई के दायरे में आए कुछ प्रमुख उदाहरणों में प्लक्ष का आम का जूस शामिल है, जिस पर नो एडेड शुगर का दावा किया गया था, जबकि जांच में उसमें गन्ने का रस पाया गया। इसी तरह, नेचुरल पनीर शब्द का इस्तेमाल भी मिश्रित खाद्य पदार्थों के लिए नेचुरल शब्द के उपयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया। मास्टरचाउ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 परसेंट नेचुरल, फ्रेशली मेड जैसे दावों और आर्गेनिक आटा के उल्लेख पर नोटिस मिला। फेरेरो इंडिया के किंडर जाय पर रिच इन मिल्क सालिड्स के दावे और मैरिको लिमिटेड के सैफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग आयल से जुड़े स्वास्थ्य दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिजेन लैब्स, नेक्सा इंडस्ट्रीज और रा प्रेसरी जैसी कंपनियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन संबंधी दावों के लिए वैज्ञानिक सबूतों की कमी पाई गई। सिर्फ भ्रामक दावों ही नहीं, बल्कि स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई हुई है। बीकानेरवाला को एक स्टाफ सदस्य के काम के घंटों के दौरान सर्विस एरिया में खाने की शिकायत पर नोटिस भेजा गया। वहीं परम डेयरी लिमिटेड को आईआरसीटीसी कैटरिंग सर्विस को सप्लाई किए गए दही और रबड़ी में फंगस मिलने के गंभीर आरोपों पर जवाब-तलब किया गया है। एफएसएसएआई ने सभी संबंधित एफबीओ को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत सुधारात्मक उपाय करें और लागू खाद्य सुरक्षा, विज्ञापन तथा लेबलिंग नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।